

संक्षिप्त समाचार

खुरीपार में संचालित अवैध खटालों को हटाने का नोटिस जारी किया गया

भिलाईनगर (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्र. 04 खुरीपार अंतर्गत औद्योगिक थेट्र में वार्ड 44 एवं 45 क्र. अमर धरम काठा में अवैध खटाल संचालित करने वाले को नोटिस तामिल करवाया गया। उनके द्वारा भारी मात्रा में गोबर व गंदी इकट्ठा कर नाली में बहाया जा रहा था।

पानी निकासी में समस्या आ रही थी। आयुक्त राजीव कुमार पांडेय को जब यह जात हुआ तब उन्होने स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अंती को निर्देशित किए कि ओके पर जाकर निरीकण करवायें। निरीकण में यथा पाया गया कि खटाल संचालक द्वारा अपने खटाल का गोबर, मल, मूत्र, गंदी एवं सड़ा हुआ भूसा को सड़क पर फैलाया जा रहा है। इससे आस-पास के रहस्यमयों को परेशानी एवं गंदी का समान करना पड़ रहा था। 15 खटालों को नोटिस जारी किया गया कि अवैध खटाल जगह से हाला तों सभी खटालों को गोकूल नगर में व्यवस्थापित किया जाएगा। समय अवधि के अंतर जो लोग खटाल नहीं हटाएं उनके ऊपर नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत करवाई जी जाएगी। प्राप्त अधिकारी के अनुसार रिहायसी क्षेत्र में सार्वजनिक सुरक्षा के अंतर्गत लोक न्यूसेंस फैलाने के कारण दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 133 के तहत अप्राप्त दर्ज करने की कार्यावाही प्रस्तुत की जावेगी। नोटिस तामिल के दौरान उपस्थित रहने वाले निरीकण किए गए थे।

भारत निर्वाचन आयोग की तीन नई पहलें, निर्वाचक नामांकितों को अपडेट करने में मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जाएगा

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामांकितों की स्टीटीकों में सुधार लाने तथा नामांकितों के लिए भवित्व प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के द्वारा एवं नई पहल की है। ये उपयोग भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं। आयोग अब निर्वाचक रिजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में यथा-संशोधित) की धारा 3(5) (ख.) के अनुरूप भारत के महापंजीकरण से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरियों (ईआरओ) के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं। आयोग अब निर्वाचक रिजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में यथा-संशोधित) की धारा 3(5) (ख.) के अनुरूप भारत के महापंजीकरण से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरियों (ईआरओ) को योग्यकृत मौतों के बारे में समय पर यह जाकरी की स्थिति अनुरूप हो जाएगी। निर्वाचक नामांकितों के लिए अपने नाम को योग्यकृत बदलने के बारे में सक्षम होंगे। मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके द्वारा एवं भी सुधार करने का फैसला किया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रभुत्वाते से प्रदर्शित की जाएगी, साथ ही फॉन का आकार भी बढ़ावा जाएगा जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदाता के बारे में बदलाव करना आसान हो जाएगा और मतदाता अधिकारियों के लिए निर्वाचक नामांकितों में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूँढ़ा आसान हो जाएगा।

सोलेशियम योजनानंतर्गत 22 लाख रुपए रो अधिक सहायता राशि स्वीकृत

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। सोलेशियम योजना (हिंट एंड रो) अंतर्गत अधिक सहायता राशि मृतक के निकट एवं पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान किया गया। योजना के तहत 1 जनवरी 2025 से 1 मई 2025 तक 12 लोगों को 22 लाख 25 हजार मुआवजा राशि प्रदान किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार चंद्रकांत साहू पिता दत्तानु साहू निवासी रिसदार तहसील बलौदाबाजार 2 लाख रुपए, योग्यश्री पति दत्तानु हण्डी सहायी अमेरा तहसील ललान 2 लाख रुपए, पुष्टमा फॉन्फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरूप की प्रतीक्षा किए जिन, फॉन्फॉर्म 7 के तहत निर्वाचक नामांकितों को संक्षिप्त एवं सक्षम होंगे। मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके द्वारा एवं भी सुधार करने का फैसला किया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रभुत्वाते से प्रदर्शित की जाएगी, साथ ही फॉन का आकार भी बढ़ावा जाएगा जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदाता के बारे में बदलाव करना आसान हो जाएगा और मतदाता अधिकारियों के लिए निर्वाचक नामांकितों में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूँढ़ा आसान हो जाएगा।

सोलेशियम योजनानंतर्गत 22 लाख रुपए रो अधिक सहायता राशि स्वीकृत

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। सोलेशियम योजना (हिंट एंड रो) अंतर्गत अधिक सहायता राशि मृतक के निकट एवं पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान किया गया। योजना के तहत 1 जनवरी 2025 से 1 मई 2025 तक 12 लोगों को 22 लाख 25 हजार मुआवजा राशि प्रदान किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार चंद्रकांत साहू पिता दत्तानु साहू निवासी रिसदार तहसील बलौदाबाजार 2 लाख रुपए, योग्यश्री पति दत्तानु हण्डी सहायी अमेरा तहसील ललान 2 लाख रुपए, पुष्टमा फॉन्फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरूप की प्रतीक्षा किए जिन, फॉन्फॉर्म 7 के तहत निर्वाचक नामांकितों को संक्षिप्त एवं सक्षम होंगे। मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके द्वारा एवं भी सुधार करने का फैसला किया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रभुत्वाते से प्रदर्शित की जाएगी, साथ ही फॉन का आकार भी बढ़ावा जाएगा जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदाता के बारे में बदलाव करना आसान हो जाएगा और मतदाता अधिकारियों के लिए निर्वाचक नामांकितों में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूँढ़ा आसान हो जाएगा।

झायरिंग लायसेंस बनवाने हेतु शिविर 3 एवं 4 मई को

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। राज्य शासन के निर्देश पर जिले में सुशासन तिहारी 2025 के तहत आम नागरिकों को द्वारा लायरिंग लायसेंस से संबंधित मांग का त्वरित निराकरण हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र में 3 एवं 4 मई 2025 को प्रातः 9 बजे से यहां लायरिंग लायसेंस बनवाने के लिए अपनी साथ आयोजित किया जाएगा। जनपद कार्यालय बलौदाबाजार, भाटापारा, पलारी, कस्डील एवं सिमाना में परिवहन सुविधा केन्द्र के माध्यम से जानकारी को लेकर लायरिंग लायसेंस बनवाने के लिए अपनी साथ आयोजित किया जाएगा।

झायरिंग लायसेंस बनवाने हेतु शिविर 3 एवं 4 मई को

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। राज्य शासन के निर्देश पर जिले में सुशासन तिहारी 2025 के तहत आम नागरिकों को द्वारा लायरिंग लायसेंस से संबंधित मांग का त्वरित निराकरण हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र में 3 एवं 4 मई 2025 को प्रातः 9 बजे से यहां लायरिंग लायसेंस बनवाने के लिए अपनी साथ आयोजित किया जाएगा। जनपद कार्यालय बलौदाबाजार, भाटापारा, पलारी, कस्डील एवं सिमाना में परिवहन सुविधा केन्द्र के माध्यम से लायरिंग लायसेंस बनवाने के लिए अपनी साथ आयोजित किया जाएगा।

झायरिंग लायसेंस बनवाने हेतु शिविर 3 एवं 4 मई को

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। राज्य शासन के निर्देश पर जिले में सुशासन तिहारी 2025 के तहत आम नागरिकों को द्वारा लायरिंग लायसेंस से संबंधित मांग का त्वरित निराकरण हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र में 3 एवं 4 मई 2025 को प्रातः 9 बजे से यहां लायरिंग लायसेंस बनवाने के लिए अपनी साथ आयोजित किया जाएगा। जनपद कार्यालय बलौदाबाजार, भाटापारा, पलारी, कस्डील एवं सिमाना में परिवहन सुविधा केन्द्र के माध्यम से लायरिंग लायसेंस बनवाने के लिए अपनी साथ आयोजित किया जाएगा।

झायरिंग लायसेंस बनवाने हेतु शिविर 3 एवं 4 मई को

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। राज्य शासन के निर्देश पर जिले में सुशासन तिहारी 2025 के तहत आम नागरिकों को द्वारा लायरिंग लायसेंस से संबंधित मांग का त्वरित निराकरण हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र में 3 एवं 4 मई 2025 को प्रातः 9 बजे से यहां लायरिंग लायसेंस बनवाने के लिए अपनी साथ आयोजित किया जाएगा। जनपद कार्यालय बलौदाबाजार, भाटापारा, पलारी, कस्डील एवं सिमाना में परिवहन सुविधा केन्द्र के माध्यम से लायरिंग लायसेंस बनवाने के लिए अपनी साथ आयोजित किया जाएगा।

झायरिंग लायसेंस बनवाने हेतु शिविर 3 एवं 4 मई को

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। राज्य शासन के निर्देश पर जिले में सुशासन तिहारी 2025 के तहत आम नागरिकों को द्वारा लायरिंग लायसेंस से संबंधित मांग का त्वरित निराकरण हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र में 3 एवं 4 मई 2025 को प्रातः 9 बजे से यहां लायरिंग लायसेंस बनवाने के लिए अपनी साथ आयोजित किया जाएगा। जनपद कार्यालय बलौदाबाजार, भाटापारा, पलारी, कस्डील एवं सिमाना में परिवहन सुविधा केन्द्र के माध्यम से लायरिंग लायसेंस बनवाने के लिए अपनी साथ आयोजित किया जाएगा।

झायरिंग लायसेंस बनवाने हेतु शिविर 3 एवं 4 मई को

बलौदाब

संपादकीय फट

न्यायपालिका पर हमले

उप-राष्ट्रपति ने संसद को सर्वोच्च बताया है। यानी संसद कोई विधेयक पारित कर सकती है, जिसका न्यायिक परीक्षण नहीं ना चाहिए। इस तरह जगदीप धनखड़ ने अवरोध एवं संतुलन की वैधानिक व्यवस्था को सिरे से नकारने की कोशिश की है। न्यायपालिका पर हमले जारी रखते हुए उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब ये विवादास्पद बात कही है कि भारतीय व्यवस्था संसद सर्वोच्च है। इस तरह उन्होंने अवरोध एवं संतुलन की वैधानिक व्यवस्था को सिरे से नकारने की कोशिश की है। धनखड़ के मुताबिक संसद के ऊपर सिर्फ मतदाता हैं, जो संसद में चुनाव करते हैं। इस तर्क को आगे बढ़ाया जाए, तो उसका अर्थ कलेगा कि निर्वाचित होने के बाद संसद कोई भी विधेयक पारित न कर सकती है, जिनमें संविधान संशोधन बिल भी शामिल हैं। यह कई सीधे तौर पर संवैधानिक अदालतों के अस्तित्व को चुनौती देता है। इसलिए कि संवैधानिक अदालतों (सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट) को संविधान ने संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या का अधिकार दिया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को संसद से पारित विधेयकों के परीक्षण का अधिकार भी हासिल है। भारत में व्याख्यास्त्र के विकास के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के नियादी ढांचे का सिद्धांत विकसित किया है। इस ढांचे से हेरफेर न करने वाले कानूनों को रद्द कर देने का अधिकार उसे हासिल है। हाई कोर संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधान है कि 'न्याय को पूर्णता प्रदान करने के लिए' सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। यह आदेश सारे देश में लागू होगा। जहां तक सर्वोच्चता का वाल है, तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में शक्तियों के अलगाव सिद्धांत अपनाया गया है। इसके तहत कोई राजकीय संस्था वर्त्तीच्च नहीं है। हर संस्था को ऐसे अधिकार हैं, जिससे वह अवरोध एवं संतुलन का दायित्व निभा सके। अवरोध एवं संतुलन की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि हर संस्था संवैधानिक दायरे का काम करे। इस तरह अधिनायकवाद की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रहता है। उप-राष्ट्रपति खुद एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं, जहां उनसे भी ऐसी भूमिका की अपेक्षा की जाती है। मगर हाल के घण्टों में उन्होंने 'न्याय को पूर्णता प्रदान करने' संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी है और अब उन्होंने संसद की वर्त्तीच्चता का एलान किया है। उनके इस नजरिए से राष्ट्रीय जनमत एक बड़े हिस्से में कौतूहल देखा गया है। ये सवाल उठा है कि अग्रिम धनखड़ ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं?

योगेंद्र योगी

पुलिस के कुक्कत्यां सिफर मनमर्जी तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाए कई गमलों खुद अपराधी बन बैठी है। पंजाब के चर्चित गोगा सेक्स स्कैंडल में मोहाली स्थित कोर्ट ने 4 पुलिसमण्डिकारियों को सजा सुनाई है। नेताओं की हाथों की उम्मीदों का उठपुलती बनी पुलिस प्रणाली देश के आम लोगों का विश्वास जीतने में पूरी तरह नाकाम रही है। पुलिस का आचरण और व्यवहार आजादी के बाद भी सामंती बना आ रहा है। अपराध रोकने की जिम्मेदारी निभाने वाली है। पुलिस के अपराधियों की तरह आचरण करने से वर्द्धी गणदार हो रही है। पुलिस राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में नियन्त्रण के कारण सत्तारूढ़ दलों के इशारों के बगैर काम ही हीं करती है। ऐसे ही हालात पुलिस पर पक्षपात करने की



साए में जेल में बिताए, जबकि पुलिस और न्यायिक व्यवस्था की नाकामी साफ़नजर आई। सुप्रीम कोर्ट पुलिस और सत्तारूढ़ दलों के नापाक गठजोड़ को कई बार उड़ागार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रहे एनवी रमना ने एक मामले में कहा था कि देखा जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर करते हैं और सत्ता पक्ष के विरोधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती जब विरोधी पक्ष के लोग सत्ता में आते हीं तो उन्हीं पुलिस अफसरों पर कार्यवाही करते हैं। देश में इस तरह का जो टेंड दिख रहा है वह कामी परेशान करने वाला है। मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा था कि इसके लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वह कानून के शासन पर टिके रहें। वह सत्ता और विपक्ष किसी के साथ न होकर स्वतंत्र रूप से काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरुजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए की थी। पाल के खिलाफ पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के इशारे पर आय से अधिक सम्पत्ति और राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कोलकाता चिकित्सक के बलात्कार-हत्याकांड की सुनवाई के दौरान कहा था कि कोलकाता पुलिस ने इस मामले को जिस तरह से संभाला, वह कुछ ऐसा है जो उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्षों में नहीं

देखा। शीर्ष अदालत ने अप्राकृतिक मौत के मामले वे पंजीकरण में देरी की आलोचना की। पुलिस कई मौजूदा कार्यप्रणाली को लेकर देश में कई सुधार करने के प्रयास हुए हैं, किन्तु सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने ऐसे प्रयासों को नाकाम करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। स्वतंत्रता के बाद से ही, इस व्यवस्था में सुधार की मांग उठती रही है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार अकुशलता और जनता में अविश्वास का कारण बनी हुआ है। पुलिस सुधारों के लिए कई आयोगों और समितियों का गठन किया गया। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977–1981) और वर्ष 1971 में बनी गोर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें धूल खा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2006 में प्रकाश सिंह मामले में पुलिस सुधारों पर कई निर्देश दिए। जिनमें यह भी शामिल था कि राज्य पुलिस प्रमुखों का दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा। निर्देशों में राज्य सुरक्षा आयोगों का स्थापना, वरिष्ठ अधिकारियों के लिये निश्चित कार्यकाल और कानून एवं व्यवस्था से जाँच को अलग करना शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी राज्यों ने पालना नहीं की। इसे देश के सभी राज्यों ने या तो लागू नहीं किया या फिर निर्देशों को आधे-अधूरे तरीके से लागू किया गया ताकि पुलिस में सत्तारूढ़ दलों का हस्तक्षेप पूरी तरह से बना रह सके। इन सिफारिशों के लागू नहीं करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 72 प्रतिशत पुलिस अधिकारियों ने मामलों की जाँच करते समय राजनीतिक दबाव का

આલોચના

व्यंग्यः आस्तीन में घर हैं जिनके

विवेक रंजन श्रीवास्तव

साशल मांडिया म खालिस भारतीय विदेशो भक्त आर उनकी दोहरे चरिट्र देखने लायक हैं। भारत के डिजिटल जंगल में इस नई प्रजाति का उदय हुआ है, जिनकी जुबान वैश्विक नागरिकता का राज अलापती है, पर भारत की आस्तीन में छुपा उनका घर किसी और ही महाद्वीप का पता बताता है। ये वो शख्सियतें हैं जो भारत की मिट्टी में पलती-बढ़ती हैं, पर उनकी नज़रें हमेशा विदेशी स्टैंडर्ड्स के पैमाने से ही देश को नापती हैं। अगर कोई भारत सरकार की आलोचना करे, तो ये उसकी पीठ थपथपाने को तैयार मिलते हैं। यदि सरकार के समर्थन में कुछ लिख दिया तो यह बिंगड़ भक्त का टाइटिल देने में देर नहीं लगाती, इस तरह वे स्वयं को कथित सेक्युलर साक्षित करने में जुट जाते हैं। विदेशी सरकारों के मुंह से भारत पर कोई टिप्पणी निकले, तो ये उसे सचाई का आईना धोषित कर देते हैं। आस्तीनों में बसे इनके घर की नींव तो शायद, न्यूयॉर्क या जेनेवा की मिट्टी से बनी हैं। इनके रहने वाली बांधी भीतर ही भीतर पाकिस्तान और बंगलादेश तक जुड़ी हुई है। इनका व्यंग्य-शस्त्रागार बेहतरीन होता है। सरकार ने कोई नीति बनाई? तुरंत दिव्यर पर ट्रेंड करो- अरे, स्वीडन में ऐसा होता तो...। किसी भारतीय संस्था ने कोई उपलब्धि हासिल की? ..पर सिंगापुर में तो ये सालों पहले...। ये लोग कॉम्पेयर एंड डिस्पेयर के मास्टर हैं। इन्हें पता ही नहीं कि स्वीडन की आबादी भारत के एक छोटे राय जितनी है, या सिंगापुर का भूगोल चंडीगढ़ से छोटा है। पर इन्हें यथार्थ से क्या लेना-देना? इनका काम वर्चुअल एक्सपर्ट बनकर अपने ही देश को लाताइना है। ये अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हैं, पर इनकी परिभाषा में आजादी सिर्फ़ सरकार की आलोचना करने तक सीमित है।

अंगर कोइ इनसे पूछे, भइ, आप जिस देश का आइडियल मानते हो, वहाँ तो पुलिस प्रोटेस्टर्स पर घोड़े दौड़ाती हैं! तो जवाब मिलता है वो अलग बात है, वहाँ की सरकार परफेक्ट है। यानी, इनके लिए आलोचना का अधिकार सिर्फ भारत के लिए रिजर्व्ड है। बाकी दुनिया?, उन्हें तो समझने की ज़रूरत है! ये विदेशी मीडिया के प्रति हैलो प्रिंसिपल सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं। ये अंग्रेजी जानते हैं, विदेशी मीडिया के प्रति बेहिसाब लगाव रखते हैं। किसी विदेशी मीडिया ने भारत पर कोई रिपोर्ट छापी, तो ये उसे गॉस्पल मानकर शेयर करते हैं। पर अंगर भारतीय मीडिया विदेशों में हो रहे अत्याचारों की बात करे, तो ये उसे प्रोगेंडा बताते हैं। इनके मुताबिक, ऑब्जेक्टिविटी की मोहर सिर्फ विदेशी चैनलों पर लगती है। और हाँ, अंगर कोई भारतीय इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठाए, तो वह अंधभक्त कहा जाता है! इनके ट्रीट्स और पोस्ट्स देखकर लगता है मानो भारत की हर समस्या का समाधान विदेशी सलाहकारों के पास है। गंगा प्रदूषण? यूरोपियन एक्सपर्ट्स को बुलाओ! किसान आंदोलन? यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए! पर इन्हें यह नहीं सूझता कि जिन देशों को ये रोल मॉडल मानते हैं, उन्होंने अपनी समस्याएँ खुद सुलझाई थीं। स्वदेशी समाधानों पर भरोसा? अरे, वो तो रिग्रेसिव है! वेस्टर्न वैलिडेशन चाटुकारिता का नया अवतार, ये लोग भारत के सॉफ्ट पावर पर तब तक शक करते हैं, जब तक कि कोई विदेशी उसे वैलिडेट न कर दे। योग? तब तक अंधिविश्वास है, जब तक यूनेस्को ने उसे विरासत न घोषित किया। आयुर्वेद? झाङ-फूँक है, जब तक हॉलीयुड सेलिब्रिटीज ने उसकी तारीफ न कर दी। इन्हें लगता है कि भारत की प्रशंसा का अधिकार सिर्फ विदेशियों के पास है। जैसे कि अपनी माँ की तारीफ पड़ोसी के मुँह से निकलना ज़रूरी हो! हो सकता है कि इन आस्तीन के सांपों का इरादा देश का भला करना हो, पर इनकी रणनीति संदेह पैदा करती है। ये भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता और राष्ट्र-विरोधी नैरेटिव में फ़र्क होता है। समस्या यह नहीं कि ये सरकार की आलोचना करते हैं; समस्या यह है कि ये एजेंडा प्रेरित टूल किट से अंध प्रवक्ता बनकर, फिर देश की आस्तीन में घुस जाते हैं।

प्रियका सौरभ

दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में गिना जाता है, गल में एक अजीबोगरीब और प्रतीकात्मक विवेरोध का केंद्र बना। कुछ छात्रों ने कलासरूपी दीवारों पर गोबर लीपा और प्रिंसिपल के गर के बाहर भी गोबर फेंक दिया।

गोबर से लीपा, बल्कि प्रिंसिपल के घर तक जाकर वहाँ भी प्रदर्शन किया।

निराशा और हताशा की उपज है जो वर्षों से भीतर ही भीतर सुलग रही है। जब संवाद के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो प्रतीकात्मक और चौंकाने वाले कदम ही विकल्प बनते हैं। यह विरोध 'हिंसक' नहीं था, लेकिन 'सुर्गधित' भी नहीं था। निश्चित रूप से गोबर से दीवारें लीपना किसी भी संस्थान के लिए अनुशासनीय हरकत मानी जाएगी। लेकिन यह भी सोचना होगा कि जब छात्र अपनी बात कहने के लिए इतना असामान्य तरीका अपनाते हैं, तो समस्या छात्रों में नहीं, व्यवस्था में भी है वे किस हृद तक खुद को असहाय और अनसुन समझाते हैं, यह इस घटना से जाहिर होता है अलवत्ता, यह विरोध मानसिक और सांस्कृतिक असहजता पैदा करने वाला जरूर था। छात्रों का प्रार्थना प्रियांग के द्वितीय पात्र प्रांत के

रहे हैं? किस घटना ने उन्हें इस हद तक पहुंचाया? किसने संवाद के रास्ते बंद किए? मीडिया अवसर लक्षणों पर बहस करता है, लेकिन बीमारी की जड़ तक नहीं जाता। सत्ता जब गाय और गोबर को संस्कृति का हिस्सा मान कर उन्हें नीतियों में शामिल करती है-जैसे गोबर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना, पंचगव्य को चिकित्सा बताना-तब वह ‘धर्म-सम्मत’ होता है।

लेकिन जब यही प्रतीक छात्रों के विरोध में आते हैं, तो वे ‘अश्लील’ और ‘असभ्य’ बन जाते हैं। यही सत्ता का दोहरापन है। छात्रों का विरोध सत्ता के इस पार्चांड की पोल खोलता है-दिखाता है कि सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग केवल सत्ता के लिए सुरक्षित नहीं है, बल्कि जनता भी उन्हें विरोध के औजार बना सकती है। इस घटना के बाहरे जरूरी हो गया है कि विविधालयों में संवाद की संस्कृति को फिर से मजबूत किया जाए। यह घटना प्रतीकात्मक चेतावनी है-शिक्षा का मंदिर यदि सत्ता की चौकी बन जाए, तो छात्र वर्षी पर ‘थुद्धि यज्ञ’ करने लगते हैं। गोबर का यह विरोध हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में असहमति की गुंजाइश बनी रहती चाहिए। बात यीताँ में भी नहीं ऐसी थी-

रहना चाहए -वरना दावार हा नहा, साच भा
गंधाने लगती है।

सुपर संसद के रूप में काम करने की इजाजत किसने दी

कमलेश पांडे

ऐसे में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप नखड़ की यह टिप्पणी वाजिब है कि नायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय करने, और 'सुपर संसद' के रूप में काम करने की इजाजत हीं दी जा सकती है, इसलिए उन्होंने इस विधय को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जो उनके प्रबुद्ध होने का परिचायक है। प्रारंतीय लोकतंत्र में विधायिका, नायपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका और समाजपालिका में पारस्परिक टक्कराव गोई नई बात नहीं है, लेकिन यह जनहित

करवाने में हमारी ससद और सवाच्चय न्यायालय दोनों असफल साबित हुए हैं और इनके ऊलजलूल तर्कों से देश इस्लामिक चरमपंथियों के नापाक मंसूबों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। राष्ट्रपति शासन, आरक्षण विवाद, भाषा विवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि सुलगते सवालों पर राष्ट्र का सही मार्गदर्शन करने में भी ये संस्थाएं विफल प्रतीत हो रही हैं। ऐसे में इनकी नकल कसने के लिए भारतीय संविधान कभी कागरा साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह खुद साप्राञ्जिवादी मानसिकता वाले विरोधाभासों से भरा पड़ा है। ऐसे में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप



खिलाफ एक परमां
जो न्यायपालिका
उपलब्ध है। बता
अनुच्छेद 142 सुप्रीम
किसी भी मामले में
करने के लिए आदेश
देता है। उहोंने यह
और कहा है कि, ‘
जो कानून बनाएंगे
काम करेंगे और उन
होगी, क्योंकि देश
नहीं होता है।’ उपराख
17 अप्रैल 2025 तिथि
हाल ही में जूडिशिय
राष्ट्रपति को निर्देश
प्रवर्ति पर ठीक ही

कहा कि समय आ गया है जब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका फ्लो-फूलें। किसी एक के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप चुनौती पैदा करता है, जो अच्छी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदी से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने ठीक ही कहा कि अगर यह घटना आम आदमी के घर पर हुई होती, तो मामले में रॉकेट की रफ्तार से एफआईआर दर्ज की जाती। जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्र जांच या पूछताल के खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि किसी संस्था या व्यक्ति को पतन की ओर धकेलने का सबसे पुखा तरीका उसे जांच से सुरक्षा की पूर्ण गारंटी प्रदान करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली हाइकोर्ट के एक जज के घर मिले कथित कैश की ओर इशारा करते हुए उस पर लीपापोती की नाजायज प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए। धनखड़ ने दो टूक शब्दों में कहा कि हाई कोर्ट के एक जज के घर से मिले कैश से जुड़े मामले में एफआईआर न होना आमलोगों के सवालों के घेरे में है। इसलिए सवाल उठाया कि क्या 'कानून से परे एक ब्रेणी' को अधियोजन से छुट है।

व्यापार समाचार

एसबीआई के साथ लैंड पोर्ट ऑथोरिटी ने साइन किया एमओयू 18 लाख से ज्यादा लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली। लैंड पोर्ट ऑथोरिटी ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) साइन किया है। इसके तहत सरकारी बैंक लैंड पोर्ट ऑथोरिटी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगी, जिसमें फैरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, कार्ड पैमेंट सर्विसेज और कॉर्पोरेट सेलेरी पैकेज शामिल हैं। इससे 18 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ व्यापारिंग बैंक मिशन ने बताया कि यह सभी बैंकिंग सर्विसेज लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के एंट्री और एरिंग्ट पॉइंट्स पर प्रदान की जाएंगी। फैरेन लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के पास 15 एंट्री और एरिंग्ट पॉइंट्स हैं और इनमें 11 और जुड़ने वाले हैं। आगे चलकर बैंक इसके हिसाब से ही अपनी सेवाओं का विताकर करेगा। उन्होंने आगे कहा कि लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के जरिए करीब 18 लाख लोग हमारे देश से बाकी देशों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जाते हैं बैंक इन सभी लोगों को जरूरी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे, जिसमें नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, फैरेन ट्रैकल कार्ड और पॉइंट्स बी शामिल होगा। इससे इलाके के लोगों को बन-स्टर्प बैंकिंग सॉल्यूशन भी मिलेगा। एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसके पास 50 करोड़ से अधिक ब्रांचों के साथ इसके पास 50 करोड़ हैं और 22,500 से अधिक ब्रांचों के साथ इसके पास 63,580 एटीएम भी हैं।

क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के हैं कई फायदे, मिलेंगे रिवॉर्ड्स

नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बीच यूनिफाइड पैमेंट्स इंटरफेस ने लेनदेन को बेहद सरल बना दिया है। अब, यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करने का विकल्प भी लोकप्रिय हो रहा है, खासकर ऋब्हवृ१ क्रेडिट कार्ड के साथ। यह एक ऐसा कदम है जो आपके भुगतान अनुभव को और भी बेहतर बना सकता है, बताएं इसका इस्तेमाल सावधानी से किया जाए। यूपीआई ने देश में पैमेंट के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। अपने ऋब्हवृ१ क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके, आप सीधे अपनी क्रेडिट लिमिट का उपयोग करके यूपीआई पैमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको हर जगह क्रेडिट कार्ड साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होती। क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक किए गए अन्य बैंकों को जरिए आप इन बूथ्या आकर्षण ऊंचे द्वारा दिया जाने वाले रिवॉर्ड्स और बैंकोंको होते हैं, जो अक्सर डैम्पिंग कार्ड से बेहतर होते हैं। ऋब्हवृ१ क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने पर आपको यूपीआई लेनदेन पर भी रिवॉर्ड पाइंट्स या कैशबैंक मिल सकता है, जिससे आपके खर्च पर बचत हो सकती है। क्रेडिट कार्ड से हर जगह पैमेंट करना, खासकर छोटी दुकानों या वेंडर्स के पास जहाँ पॉइंट्स मर्शिन नहीं होती, मुश्किल हो सकता है। लेकिन यूपीआई बूथ्या कोड लगभग हर जगह उत्तम रूप है। यूपीआई से लिंक किए गए अन्य बैंकों को जरिए आप इन बूथ्या आकर्षण ऊंचे द्वारा दिया जाने वाले रिवॉर्ड्स और अन्य बैंकों को जरिए आपके अन्य बैंकों के साथ ही अपने बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के कर्तव्यों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। जब तक कि एक स्थायी सीईओ की नियुक्ति नहीं हो जाती। बैंक ने बूथ्याकरों को यह कदम इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुमत कर्पोरेट अकाउंटिंग में चुक को लेकर अपने पद से इस्तीफा देने के बाद उठाया गया है। यह समिति की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष करते हैं और इसमें अॉफिसियल समिति, मुआवजा, नामांकन और पारिश्रमिक की नेटवर्क में गिरावट आई है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग

पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 20 लोग गिरफतार

मांगलुरु। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले और देशभर में फैले गुरुसे के माहौल के बीच कर्नाटक के मांगलुरु जिले से एक विचलित करने वाली घटना समाप्त आई है। यहाँ पाकिस्तान जिदाबाब के नारे लगाने के आरोप में भीड़ ने एक दिवाही मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 20 लोगों को गिरफतार किया है।

पुलिस ने बूथ्याकरों को बताया कि मृतक की पहचान करले के वायनाड निवासी अशरफ (ह्यूडलहुड) के रूप में हुई है। अशरफ मांगलुरु में मजदूरी का काम करता था। पुलिस ने इस हत्या के संबंध में अब तक 20 आरोपियों को गिरफतार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि इस घटना में शामिल अन्य 5 आरोपियों की तलाश जारी है।

यह घटना बीते रविवार की शाम करीब 5.30 बजे उस समय प्रकाश में आई जब पुलिस को कड़वु पालके में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। शुरुआती तौर पर शव पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं दिख रहा था, जिसके चलते पुलिस ने शुरुआत में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था और शव को पोस्टमार्टेंट के लिए वेनलाक जिला अस्पताल भेजा गया था। कूलशेखर निवासी दीपक कुमार ने इस मामले में पुलिस की शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने घटना स्थल से मिले सुरामों और सोशल मीडिया पर साझा किए गए तस्वीरों और वीडियो के अनुसार एर आरोपियों की पहचान की और उनकी धरपकड़ शुरू की। पुलिस को शुरुआती जांच और आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि क्रिकेट मैच देखने के दौरान अशरफ ने कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। इससे वह मौजूद करीब 25 युवक भड़क गए और उन्होंने अशरफ पर हमला कर दिया।

सरकारी प्रोत्साहन और इंफारस्ट्रक्चर में निवेश से ईवी को तेजी से अपना रहे भारत के लोग : रिपोर्ट



एसबीआई के साथ लैंड पोर्ट ऑथोरिटी ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) साइन किया है। इसके तहत सरकारी बैंक लैंड पोर्ट ऑथोरिटी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगी, जिसमें फैरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, कार्ड पैमेंट सर्विसेज और कॉर्पोरेट सेलेरी पैकेज शामिल हैं। इससे 18 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ व्यापार देवेलपर मिशन ने बताया कि यह सभी बैंकिंग सर्विसेज लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के एंट्री और एरिंग्ट पॉइंट्स पर प्रदान की जाएंगी। फैरेन लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के पास 15 एंट्री और एरिंग्ट पॉइंट्स हैं और इनमें 11 और जुड़ने वाले हैं। आगे चलकर बैंक इसके हिसाब से ही अपनी सेवाओं का विताकर करेगा। उन्होंने आगे कहा कि लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के जरिए करीब 18 लाख लोग हमारे देश से बाकी देशों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जाते हैं बैंक इन सभी लोगों को जरूरी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। एसबीआई के शीर्ष अधिकारी ने आगे बताया कि हमारे पास 11 ब्रांच हैं और अपनी पहुंच बढ़ने के लिए नई ब्रांच या बैंकिंग सेवाएं आउटलेट खोलेंगे। मिशन के अनुसार, भारत के यात्री बायां (वी) को 2030 के लक्ष्य के कार्यबद्धता वैराग्य और बैंकिंग सेवाएं आउटलेट खोलेंगे। यह एक ब्रांच के अनुसार, भारत के यात्री बायां (वी) को 2024 में सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़कर 4.3 मिलियन यूनिट से अधिक हो गई। इस कुल पीवी व्यक्ति में बैंकिंग वाहनों (वी) की 2.5 प्रतिशत

प्रतिशत ईवी पैनेट्रेशन हासिल करना है। आंटोमोटोट्रैक बाजार विलोपक अधिक मुख्यों के अनुसार, आंटोमोटोबाइक अधिक वृद्धि को दर्शाता है। यात्री बौद्धिकी की विक्री में वृद्धि का श्रेष्ठ कर नए मॉडलों के लॉन्च को दिया जा सकता है, जिनमें यात्रा कर्व-ईवी, एसजी विंडसर, बीवाईडी सील, बीवाईडी और ईमैट्रेशन शामिल हैं। भारत के बढ़ते कंपोनेट्स नियत के लिए एक खतरा पैदा करती है। हालांकि, यह दूसरे यात्रारों में कंपोनेट्स के लिए एक खतरा पैदा करता है। भारत के सरकार ने एक व्यापक वित्ती व्यापार का अन्याने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस लक्ष्य के तहत 2030 तक यात्री वाहन सेगमेंट में 30 प्रतिशत, संयुक्त दोषियों और तिपहिया सेगमेंट में 80 प्रतिशत और व्यापक वाहन सेगमेंट में 70 प्रतिशत ईवी पैनेट्रेशन हासिल करना है। आंटोमोटोट्रैक बाजार विलोपक अधिक मुख्यों के अनुसार, आंटोमोटोबाइक अधिक वृद्धि को दर्शाता है। यात्री बौद्धिकी की विक्री में वृद्धि का श्रेष्ठ कर नए मॉडलों के लॉन्च को दिया जा सकता है, जिनमें यात्रा कर्व-ईवी, एसजी विंडसर, बीवाईडी सील, बीवाईडी और ईमैट्रेशन शामिल हैं। भारत के बढ़ते कंपोनेट्स नियत के लिए एक खतरा पैदा करती है। हालांकि, यह दूसरे यात्रारों में कंपोनेट्स के लिए एक खतरा पैदा करता है। भारत के सरकार ने एक व्यापक वित्ती व्यापार का अन्याने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस लक्ष्य के तहत 2030 तक यात्री वाहन सेगमेंट में 30 प्रतिशत, संयुक्त दोषियों और तिपहिया सेगमेंट में 80 प्रतिशत और व्यापक वाहन सेगमेंट में 70 प्रतिशत ईवी पैनेट्रेशन हासिल करना है। आंटोमोटोट्रैक बाजार विलोपक अधिक मुख्यों के अनुसार, आंटोमोटोबाइक अधिक वृद्धि को दर्शाता है। यात्री बौद्धिकी की विक्री में वृद्धि का श्रेष्ठ कर नए मॉडलों के लॉन्च को दिया जा सकता है, जिनमें यात्रा कर्व-ईवी, एसजी विंडसर, बी

